हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-25 शिमला शुक्रवार,05 l: 11 viy 2024 आरएनआई एचपीएचआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

मंदिर में आग लगाने के शक में व्यक्ति की पीट–पीटकर हत्या

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते सप्ताह एक व्यक्ति की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने हत्या के बाद व्यक्ति का शव जला दिया। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। राजधानी से सटी गलोट पंचायत में एक कामगार युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसके शव को जलाने के सनसनीखेज मामले में एक चश्मदीद गवाह सामने आया है।

चश्मदीद ने पुलिस जांच में खुलासा किया है कि 21 मार्च को कुछ लोगा. ने टिकमचंद (38) और उसके साथ (चश्मदीद से) मारपीट की थी। लोगा. से मारपीट का कारण पूछा तो बताया गया कि उन्होंने मंदिर में आग लगाई थी जिससे भड़के कुछ लोगों ने उन दोनों को बुरी तरह पीट दिया था।

पुलिस के अनुसार, सुन्नी के मझोल गांव की तारा देवी ने बालूगंज थाने में दी शिकायत में बताया है कि उनका बेटा टीकमचंद (38) 8–9 सालों से पनेश के खरयाड़ गांव में सेवाराम के घर में काम करता था। 26 मार्च को सेवाराम की पत्नी प्रभा ने तारा देवी को फोन कर बताया कि गिरने के कारण उनके बेटे की मौत हो गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल सहित श्मशानघाट से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसमें ब्लड और मिट्टी के सैंपल सहित हड्डियों के अवशेष शामिल हैं। एफएसएल टीम को मंदिर की दीवारा. पर खून के धब्बे मिले हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा डीएनए मिलाने के लिए मृतक की मां के खून के नमूने जांच के लिए एफएसएल भेजे हैं।

मां को सूचना दिए बगैर शव जलाया

टीकमचंद की मौत हो जाने से ग्रामीण घबरा गए थे। इसलिए, उन्होंने मृतक के परिजनों को सूचित किए बगैर ही 22 मार्च को उसका शव जला डाला। फिर 4 दिन बाद यानी 26 मार्च को उसकी मां को सूचना दी गई कि उनका बेटा मर गया है। उसका कारण उन्होंने फिसलकर गिर जाना बताया।

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या और साक्ष्य मिटाने की जानकारी मिली है। तब मामला दर्ज किया है। मृतक टीकमचंद कुंवारा था। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। टीकमचंद ही मजदूरी कर अपना और अपनी मां का भरण–पोषण कर रहा था।

15&15 करोड़ में बिके कांग्रेस के बागी विधायक - मुख्यमंत्री सुक्खू

vkdlk ÅukA हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक 15–15 करोड़ रुपए में बिके हैं। उनके पास इसके प्रूफ भी हैं। ऊना जिले में गुरुवार को जनसभा संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आपकी भावना बेचकर जाते हैं, आपकी विधायकी नीलाम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, बागी विधायकों ने अपना ईमान बेचा है। ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इनकी भ्रष्टाचार से की हुई कमाई जनता की है और जनता में बंटनी चाहिए। जो लोग 14 महीने में ही बिक गए, वह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, उनकी जमानत जब्त करा देंगे। राजनीति से ऐसी गंदगी वोट देकर साफ करने की जरूरत है।

कांग्रेस के बागी 6 विधायक जो अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इन पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने 15–15 करोड़ रुपए में बिकने के आरोप लगाए हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने नोट के दम पर कुर्सी हथियाने की कोशिश की

सुक्खू ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नोट के दम पर कुर्सी हथियाने की कोशिश की है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। ऐसा आदमी आपको लूटेगा।

उन्होंने कहा कि 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर कहते हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बनेगी। उन्हें यह समझ नहीं कि जो विधायक कांग्रेस में बिक सकते हैं, वह आने वाले समय में किसी भी मंडी में नीलाम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशक हमारे पास धन नहीं है, लेकिन जनता के वोट से कांग्रेस 6 की 6 सीटें जीतेगी। राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों ने किया था क्रॉस वोट

बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल–स्पीति से रवि ठाकुर, कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो, गगरेट से चौतन्य शर्मा और धर्मशाला से सुधीर शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया।

इससे बहुमत वाली कांग्रेस सरकार राज्यसभा चुनाव हार गई।

यही नहीं इससे सरकार पर भी कुछ समय के लिए संकट आ गया था।

कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार को कोई खतरा नहीं है।

कांग्रेस को सिर्फ एक विधायक की जरूरत है, जबकि भाजपा को 10 विधायक चाहिए।

यदि स्पीकर 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो भी 9 सीटों पर उप–चुनाव होगा।

पीएचडी की अजा सीट सामान्य वर्ग से भरने पर घमासान शुरू

vkdlk f'keykA हिमाचल विश्व. विद्यालय शिमला के वाणिज्य विभाग में पीएचडी की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट को सामान्य श्रेणी से भरने के विरोध में छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। छात्र संगठन इस प्रवेश को अवैध करार देकर इसे तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एबीवीपी ने जहां वीरवार को इस मुद्दे को लेकर डीएस कार्यालय में प्रदर्शन किया वहीं एसएफआई ने भी इसको लेकर परिसर में विरोध जताया। विवि प्रशासन की ओर से इस मामले पर अब तक आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

एसएफआई की विवि इकाई ने वाणिज्य विभाग में एसटी की सीट को बदलकर सामान्य वर्ग से भरे जाने को लेकर डीएस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। एसएफआई की विवि इकाई ने वीरवार को भी प्रदर्शन किया और विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सचिवालय सदस्य रितेश ने कहा कि वाणिज्य विभाग में पीएचडी प्रवेश में अनुसूचित जनजाति की सीट को खत्म किया है और इस सीट को जनरल कैटेगरी में भरा गया है जिसका एसएफआई विरा. ध कर रही है।

परिसर सचिव सन्नी सेक्टा ने कहा की यह सीधे तौर पर एसटी छात्रों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है। एसटी छात्रों को शिक्षा के समान अधिकार से दूर किया जाना और संविधान की अनदेखी है। सचिव सन्नी ने कहा कि विश्वविद्यालय को लगातार धांधलियों का अखाड़ा बनाया जा रहा है। पूर्व के कुलपति पहले अपने और अन्य दोस्त अधिकारियों के बच्चों के पात्रता पूरी न करने के बावजूद फर्जी तरीके से प्रवेश दिलवाया।

सेब बागवानों ने, इंपोर्ट ड्यूटी 100 प्रतिशत करने और एमआईएस् की बकाया पेमेंट का जल्द भुगतान करने की दी चेतावनी

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने बुधवार को शिमला में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को घेरने की रणनीति बनाई। सेब उत्पादक संघ के अधिवेशन में मुख्यत एप्पल पर इंपोर्ट–ड्यूटी बढ़ाकर 100 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की गई, क्योंकि आयातित सेब के कारण हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की एप्पल इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

44 देशों से आयात किए जा रहे सेब के कारण हिमाचल के बागवानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे। इसलिए बागवान एक दशक से भी ज्यादा समय से सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100 फीसदी करने की मांग करते आ रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100 प्रतिशत करने का वादा किया था। मगर आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। बढ़ाना तो दूर कुछ देशों से इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा रही है।

बीते साल ही केंद्र ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 75 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत की है। इससे बीते सेब सीजन के दौरान सबसे ज्यादा मार उन बागवानों पर पड़ी है, जिन्होंने अपना सेब कोल्ड स्टोर में रखा था।

ब्लॉक स्तर पर होंगे अधिवेशन–सोहन

सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में बागवान भाजपा से इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सवाल पूछेंगे। इसके लिए 30 अप्रैल तक सभी ब्लॉक में अधिवेशन कराए जाएंगे। इनमें बागवानों को बताया जाएगा कि किस प्रकार उनके हकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कीटनाशक, फूफूंदनाशक और खादों पर सब्सिडी खत्म की जा रही है। मंडी मध्यस्थता योजना का बजट केंद्र ने बंद कर दिया है।

मंडी मध्यस्थता के तहत 90 करोड़ नहीं दे रही कांग्रेस सरकार

सोहन ठाकुर ने बताया कि हिमाचल सरकार जहां महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए 800 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान कर रही है, वहीं बागवानों की मंडी मध्यस्थता योजना के तहत दो साल से पेंडिंग 90 करोड़ की पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा। कांग्रेस सरकार को बागवान चुनाव के दौरान इस मुद्दे को लेकर घेरेंगे।

सोहन ठाकुर ने कहा– भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन यूनिवर्सल कार्टन लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बागवानों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू करने और इसे लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

एपीएमसी एक्ट सख्ती से लागू किया जाए,सरकार एपीएमसी एक्ट को सख्ती से लागू नहीं कर रही है। इससे मंडियों में किसानों–बागवानों से लूट जारी है।

उन्होंने बताया कि आज के अधिवेशन में एपीएमसी एक्ट के सभी प्रावधान सख्ती से लागू करने की बागवानों ने मांग उठाई।

शिमला में मंदिर के पुजारी ने युवती से की अश्लील हरकते

vkdlk f'keykA शिमला के शिवकुटी मंदिर में युवती से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोप मंदिर के पुजारी पर लगे हैं। शिमला पुलिस ने बालूगंज थाना में पुजारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शिमला के आईएसबीटी बस अड्डे के साथ लगते शिवकुटी रामनगर मंदिर में शिमला में बी–कॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा रविवार को मंदिर में सेवा के लिए गई थी। इस दौरान मंदिर के पुजारी भगवती प्रसाद कमोटी ने उससे अश्लील हरकतें की और गंदे–गंदे इशारे किए।

युवती के अनुसार, मंदिर का पुजारी पहले भी झाड़–फूंक के बहाने भी कई बार हरकतें करता रहा है।

पुजारी ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

पुजारी उत्तराखंड का रहने वाला है

मंदिर का पुजारी उत्तराखंड के गढ़वाल का रहने वाला बताया जा रहा है। वह काफी समय से शिवकुटी मंदिर में पुजारी है और वह परिवार के साथ शिमला में रहता है।

पुलिस युवती के बयान कलमबद्ध कर आरोपी पुजारी से पूछताछ कर रही है।

हिमाचल में जानें किस चुनाव में क्या हुआ न झाड़ू चल पाया और न हाथी

vkdlk f'keykA हिमाचल में लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई भी तीसरा दल अपना दम नहीं दिखा पाया। हालांकि, हिमाचल विकास कांग्रेस (हिविकां) ने एक बार जरूर एक सीट जीती थी, लेकिन इसका कारण भी भाजपा के साथ गठबंधन रहा। बाकी दल सभी चुनावों में तीन फीसदी मत लेने की स्थिति में भी नहीं रहे।

माकपा, बसपा, आप समेत कई पार्टियों ने प्रदेश में जड़ें जमाने के प्रयास किए, लेकिन पार्टियां खाता भी नहीं खोल सकीं।

लोकसभा चुनाव में अक्सर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच ही मुकाबला होता रहा। तीसरे मोर्चे के रूप में अपने आप को स्थापित करने उतरे बाकी दलों के प्रत्याशी चुनावों में तीन फीसदी से ज्यादा मत हासिल नहीं कर पाए।

सबसे अधिक मत प्रतिशतता आप प्रत्याशी डॉ. राजन सुशांत की तीन फीसदी ही रही, जबकि वे कांगड़ा से भाजपा से सांसद निर्वाचित हुए थे।

1980 से पहले भाजपा नहीं थी तो जनता पार्टी से जरूर सांसद बने।

1999 में हिमाचल विकास कांग्रेस यानी हिविकां ने भाजपा के सहयोग से शिमला में धनीराम शांडिल को उम्मीदवार बनाया था और वह जीत हासिल करने में कामयाब रहे।

भाजपा और कांग्रेस से इतर किसी पार्टी से सांसद बनने वाले वह पहले नेता थे।

1980 के बाद से कांग्रेस और भाजपा में ही स्पर्धा लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी से वर्ष 1977 में गंगा सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र, बालक राम कश्यप शिमला, ठाकुर रणजीत सिंह हमीरपुर ससंदीय और कंवर दुर्गा चंद कांगड़ा संसदीय सीट से सांसद बने थे।

कांग्रेस तो शुरू से ही सक्रिय थी। 1980 में जनता पार्टी के बाद भाजपा अस्तित्व में आई तो तबसे से दोनों दलों में ही स्पर्धा है। हिमाचल प्रदेश में माकपा, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, पीआरआईएसएम, आरडब्ल्यूएस, एसएचएस, एआईआईसीटी, दूरदर्शी पार्टी, जेपीएस, एलआरपी, आईएनसीओ, सोशलिस्ट पार्टी, केएमपीपी, एबीजेएस, लोजपा जैसे दल चुनाव में प्रत्याशी देते आए हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी।

मंडी संसदीय सीट

1977 में गंगा सिंह जनता पार्टी से सांसद बने।

2019 में दलीप सिंह खड़े हुए तो उन्हें 14,838 वोट पड़े।

2019 में बसपा से सीसराम ने चुनाव लड़ा, उन्हें 9,060 मत पड़े।

2014 में मंडी से माकपा से कुशाल भारद्वाज को 13,965 मत पड़े, आप के जयचंद ठाकुर को 9,359 और बसपा के लाला राम को 21,780 मत पड़े।

2009 में मंडी से डॉ. ओंकार शाद ने माकपा से चुनाव लड़ा। 20,664 वोट पड़े।

1991 में जनता दल से कर्म सिंह खड़े हुए तो उन्हें 18,112 मत पड़े।

शिमला संसदीय सीट

1977 में बालक राम कश्यप जनता पार्टी से सांसद बने

1999 में धनीराम शांडिल हिविकां से चुने गए

2014 में आप के उम्मीदवार सुभाष चंद्र को 14,233 मत और माकपा के जगतराम को 11,434 मत पड़े।

2009 में बसपा के सोमनाथ ने लिए 8,160 वोट पड़े

कांगड़ा संसदीय सीट

1977 में कंवर दुर्गा चंद जनता पार्टी से सांसद बने।

2019 में बसपा के डॉ. केहर सिंह को 8,866 मत पड़े।

2014 में आप के राजन सुशांत को 24,430 मत पड़े।

2009 में बसपा से नरेंद्र सिंह पठानिया को 12,745 वोट पड़े।

2004 में बसपा के शक्ति चंद चौधरी को 10,860 मत पड़े और सपा के रोशन चंद राणा को 7,092।

हमीरपुर संसदीय सीट

1977 में ठाकुर रणजीत सिंह जनता पार्टी से सांसद बने।

2014 में यहां पर आप प्रत्याशी कमल. कांत बत्रा को 15,329 मत पड़े।

2009 में बसपा के मंगत राम शर्मा को 11,774 वोट पड़े।

प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा तीसरी से पांचवी तक के विद्यार्थी

vkdlk f'keykA राज्य के प्राथमिक स्कूलों में सरकार की ओर से शुरू किए संस्कृत विषय के फैसले को वापस ले लिया गया है। इसको लेकर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले को प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि कई स्कूलों में मात्र एक अध्यापक तैनात है। संस्कृत विषय लागू होने के बाद उन पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ बढ़ गया था। चिंताजनक यह भी था कि अध्यापकों को संस्कृत विषय की अधिक जानक. ारी भी नहीं है।

जानकारी के अनुसार हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संस्कृत विषय की किताबें भी छपकर स्कूलों में आ गई हैं। इस बीच अब विषय हटाने का निर्णय लिया गया है। जिले में प्राथमिक स्कूल पहले ही अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऊपर से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सहित कुल आठ कक्षाएं और एक संस्कृत का अन्य विषय भी लाद दिया गया। इससे अध्यापकों और बच्चों को भारी परेशानियों का वर्षभर सामना करना पड़ा।

वर्ष 2023 में अध्यापकों और बच्चों की दिक्कतों के संबंध में प्रशासन से मुद्दा उठाया गया था।

इसका शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समाधान करने का आश्वासन दिया था, जिसका असर अब देखने को मिला है।

प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान राक. `श शर्मा, महासचिव सतेंद्र मिन्हास, सभी खंडों के प्रधान और अन्य प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा का कहना है कि कक्षा तीसरी से पांचवीं तक बीते शैक्षणिक सत्र में संस्कृत का विषय शुरू किया गया था, लेकिन बच्चों और अध्यापकों को मुश्किलों की वजह से इसको बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को लगाई फटकार

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–21 की हालत नहीं सुधारे जाने पर एनएचएआई समेत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण गिरा मलबा नहीं उठाया गया है। जुलाई में बरसात शुरू हो जाएगी। हाईवे की हालत सुधारने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

एनएचएआई और पीडब्लूडी एक दूसरे के हाथ में गेंद फेंक रहे हैं और इन दोनों के बीच आम जनता परेशान हो रही है। अदालत ने कहा कि सड़क पर उड़ रही धूल और खराब हालत गाड़ी चालकों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कुछ स्थानों पर भूस्खलन से सड़क तंग हो गई है, जिस पर तुरंत प्रभावशाली कार्रवाई करने की जरूरत है। अदालत ने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए कि वह स्पष्ट करे कि अभी तक सड़क की हालत क्यों नहीं सुधारी गई। अदालत ने प्रदेश सरकार और एनएचएआई को बरसात से पहले सड़क की मरम्मत पूरा करने के आद. `श दिए। साथ ही सभी मुद्दों पर एनएचएआई से अगली सुनवाई तक नया हलफनामा दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

कैथलीघाट–सोलन एनएच की मांगी ताजा स्टेटस रिपोर्ट

हिमाचल हाइकोर्ट ने कैथलीघाट–सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर अदालत के आदेश की अनुपालना के लिए एनएचएआई और पुलिस महा. निदेशक (डीजीपी) को ताजा रिपोर्ट दायर करने को कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के कारण लोगों के बीच आपसी विवाद का निपटारा करने के लिए दो हते के अंदर बैठक करने के निर्देश दिए।

बिकाऊ और खाऊ विधायक नहीं चलेंगे – सीएम सुक्खू

vkdlk ÅukA कांग्रेस के बागी विधायक देवेंद्र भुट्टो के विधानसभा क्षेत्र कुटलैहड़ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बागियों और भाजपा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि बिकाऊ और खाऊ विधायकी करने वाले विधायक नहीं चलेंगे। यह सच और झूठ की लड़ाई है। झूठ परस्त होगा और सच की ही जीत होगी। ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूरकलां में गुरुवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि मैं सच के साथ खड़ा हूं। विधानसभा की 6 सीटों के साथ लोकसभा की चारों सीटें भी जीतेंगे।

उन्होंने कहा कि यह वक्त टिकट की लड़ाई का नहीं है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। टिकट के सभी दावेदार, कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर जीत हासिल करने के लिए अपने–अपने क्षेत्र में जुट जाएं। वह खुद भी हर एक विधानसभा क्षेत्र की पंचायत और गांव का भी दौरा करेंगे। इस बार धनबल नहीं, जनबल हमारे साथ है। भाजपा हमेशा ही धनबल की राजनीति करती आई है। चुनावों में जनबल ही भाजपा को आईना दिखाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के जाने के बाद भाजपा में विद्रोह हो गया है।

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पहले अपना कुनबा संभाले। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने अपनी विधायकी बेची है, वह सेवा भाव से राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि लूटपाट करने आए हैं और यह बिकाऊ विधायक न तो कांग्रेस पार्टी में चलेंगे और न ही बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदा. धिकारी व कार्यकर्ता इनको टिकने देंगे। सीएम ने कहा कि हाईकमान ने सर्वे करवाया है। दावेदारों की लिस्ट ज्यादा है, लेकिन जो सर्वे में सबसे ऊपर आए हैं, उनके साथ सभी दावेदारों को एकजुट होकर चुनाव लडना है और भाजपा को सबक सिखाना है।

भाजपा को ले डूबेंगे नवग्रह

सीएम ने कहा कि इन बिकाऊ विधायकों की भ्रष्टाचार ही एकमात्र कमाई है। बीजेपी में शामिल करने के बाद भाजपा के लोग अब खुद परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि यह नवग्रह अब भाजपा को भी ले डूबेंगे। उन्होंने कहा कि 35 साल के राजनी. तिक जीवन के सफर में ऐसी दूषित राजनीति पहली बार देखने को मिली है। जब हिमाचल में आपदा आई तो केंद्र ने एक पैसे की भी मदद नहीं की। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलना हुआ। लेकिन राहत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। इसके चलते केंद्र सरकार के आगे नहीं झुके।

जब भी घर जाता हूं, मां मुझे देती है 500 रुपये

सीएम ने कहा कि जब भी मैं घर जाता हूं तो मां अपनी पेंशन से 500 रुपये देती है। कहती है कि बेटा पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों के साथ न्याय किया है। आपदा में जो काम किया है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी सराहना की है। सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो आपदा और बचाव कार्यों के लिए भी नियम बदल डाले।

आठ एचएएस सहित 26 अधिकारियों के पद भरने के लिए मांगे आवेदन

vkdlk f'keykA राज्य लोकसेवा आयोग ने आठ एचएएस सहित 26 अधिकारियों के पद भरने को आवेदन आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को आयोग ने 2 मई तक पोर्टल खोल दिया है। तहसीलदार के नौ, जिला खाद्य नियंत्रक के दो, जिला कल्याण अधिकारी के तीन, जिला पंचायत अधिकारी का एक और सहायक पंजीयक सहकारी सभा के तीन पद भरे जाएंगे। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एचएएस अधिकारियों के सामान्य श्रेणी से तीन, अनुसूचित जाति से दो, ओबीसी से एक, अनुसूचित जाति के एक्स सर्विस कोटे से एक और सुनने में अक्षम कोटे से एक पद भरा जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत जिला नियंत्रक के दो भरे जाएंगे। इसमें एक पद ओबीसी और एक आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से भरा जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत सामान्य श्रेणी से जिला कल्याण अधिकारियों के तीन पद भरे जाएंगे। राजस्व विभाग में 9 तहसीलदारों, पंचायतीराज विभाग में जिला पंचायत अधिकारी का एक और सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी सभा के तीन पद भरे जाएंगे।

प्रत्याशियों की किस्मत लिखेंगी महिलाएं छह में से तीन विधानसभा क्षेत्रों में

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में छह में से तीन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महिलाएं करेंगी। सुजानपुर, बड़सर और लाहौल स्पीति में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है।

सुजानपुर में 1,982, बड़सर में 1,472 और लाहौल स्पीति में पुरुषों के मुक. ाबले 49 महिला वोटर ज्यादा हैं। धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल–स्पीति, बड़सर, गगरेट और कुटलैहड़ में उपचुनाव होना है।

उपचुनाव में कुल 4, 48,110 मतदाता अपने नुमाइंदे चुनेंगे।

सुजानपुर में कुल 76,943 मतदाता हैं। इनमें पुरुष 36,439 और महिलाओं की संख्या 38,421 है।

बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कुल 88,445 मतदाता हैं।

इनमें 42,538 पुरुष और 44,010 महिला मतदाता हैं।

इसी तरह विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति में भी महिला मतदाता अधिक है।

यहां कुल 25,737 मतदाताओं में से 12,549 महिलाएं हैं।

जबकि पुरुष 12,500 हैं। धर्मशाला में 84,074, गगरेट में 84,975 और कुटलैहड़ में 87,936 मतदाता हैं।

इन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है।

यहां की चुनावी जमीन दिग्गजों की पसंद रही, मौलाना आजाद मायावती और मुलायम से लेकर ये दिग्गज लड़ चुके चुनाव

e|jknkcknA रामपुर से मौलाना आजाद, मुख्तार अब्बास नकवी, बिजनौर से मायावती और संभल से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ चुके हैं।

मुरादाबाद मंडल की जमीन सियासी दिग्गजों की पसंद रही है।

यहां से चुनाव लडऩे के बाद कई नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर में बुलंदियां हासिल कीं तो कुछ ने बुलंदियों पर रहते हुए मुरादाबाद मंडल से चुनाव लड़ा। इनमें भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस चारों प्रमुख दलों के बड़े चेहरे शामिल रहे हैं।

मुरादाबाद मंडल की संभल लोकसभा सीट से सपा के संस्थापक व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव दो बार चुनाव लड़ चुके हैं।

उन्होंने 1998 व 1999 में इस सीट से बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। संभल लोकसभा सीट से ही भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह 1999 में मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे।

इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

मंडल की बिजनौर लोकसभा सीट से 1989 में बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनाव लड़ चुकी हैं।

इसमें उन्हें बड़े अंतर से जीत मिली थी।

इसके अलावा 2019 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शायर इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़ चुके हैं।

यहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था।

इन चारों दलों के नेताओं में यदि मुलायम सिंह यादव को छोड़ दिया जाए तो चुनाव के समय किसी के पास पार्टी में बहुत बड़ा पद नहीं था। जबकि मुरादाबाद मंडल से चुनाव लडऩे के बाद इनके राजनीतिक कद में बढ़ोतरी होती चली गई।

अबुल कलाम आजाद

अबुल कलाम आजाद ने पहला लोकसभा चुनाव रामपुर से लड़ा। उन्होंने पहली लोकसभा के चुनाव में 108180 वोट पाए थे, जोकि 59.57 प्रतिशत थे। आजाद कांग्रेस के बड़े नेता थे।

1923 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।

रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने।

पहले लोकसभा चुनाव में बहुत कम प्रत्याशियों ने इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी।

मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव इन प्रत्याशियों में अकेले ऐसे नेता हैं, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दो बार मुख्यमंत्री रहते हुए संभल से चुनाव लड़े।

1998 में संभल लोकसभा सीट से उन्हें 376828 वोट मिले, जोकि 50.04 प्रतिशत थे।

1999 में फिर संभल लोकसभा से उन्हें सांसद चुना गया।

इस बार 259403 वोटों पर उन्होंने कब्जा किया, जोकि 41.85 प्रतिशत थे। मुलायम सिंह यादव 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।

मायावती

चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकीं मायावती के पास 1989 में बसपा में बड़ा पद नहीं था।

उस समय कांशीराम पार्टी के अध्यक्ष थे।

मायावती ने 1989 में बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा।

उन्होंने 183189 वोट पाए और जनता दल के मंगलराम प्रेमी को हराया।

मायावती को इस चुनाव में 37.96 प्रतिशत वोट मिले थे।

इसके बाद उनका कद पार्टी में बढ़ता चला गया। आज वह बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

चौधरी भूपेंद्र सिंह

मुरादाबाद से ही ताल्लुक रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह ने 1999 में संभल लोकसभा सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

उस समय उनके पास भाजपा में बड़ा पद नहीं था। वह जीत नहीं सके लेकिन पार्टी में उनका कद बढ़ता गया।

चौधरी भूपेंद्र सिंह योगी सरकार के दोनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे। पंचायती राज विभाग संभाला। बाद में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी।

इमरान प्रतापगढ़ी

शायर इमरान प्रतापगढ़ी 2019 में कांग्रेस के लिए मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे।

उस समय पार्टी में उनके पास कोई पद नहीं था।

इमरान को चुनाव में 59198 वोट मिले थे, जोकि 4.62 प्रतिशत थे। इमरान ने 2019 के चुनाव में भावुक होकर कहा था कि मैं बाहरी नहीं हूं।

करारी हार के बावजूद कांग्रेस में उनका कद तेजी से बढ़ता चला गया।

आज वह राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

मुख्तार अब्बास नकवी

मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1998 में रामपुर से लड़ा और 265116 वोट पाकर जीत गए।

ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर संसद पहुंचा हो।

इसके बाद मुख्तार अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बन गए। नकवी 2010 से 2016 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे।

2014 की मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बने।

2016 में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला।

मई 2019 में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने।

ये दिग्गज भी मुरादाबाद मंडल से लड़ चुके हैं चुनाव।

आचार्य जेबी कृपलानी, मीरा कुमार, रामगोपाल यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जयाप्रदा, आजम खां।

पंजाब पिछड़ रहा तकनीकी शिक्षा में, इंजीनिरिंग कॉलेजों में भर रही केवल 50 फीसदी सीटें

pMhx<A कभी तकनीकी शिक्षा में डंका बजाने वाला पंजाब अब लगातार पिछड़ रहा है। पंजाब के तकनीकी शिक्षा कॉलेज वीरान हो रहे हैं। पंजाब के छात्र तकनीकी शिक्षा लेने के लिए छात्र या तो अन्य प्रदेशों का रुख कर रहे हैं या फिर कनाडा, ब्रिटेन आदि के विश्वविद्यालयों की तरफ भाग रहे हैं। 50 फीसदी सीटें ही भर पा रहीं हैं। नतीजन, पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेजों के हाल बेहाल हैं। इससे राज्य के 300 से अधिक तकनीकी कॉलेजों में लगभग 55 प्रतिशत सीटें बेकार हो रही हैं।

राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालय–आईके गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्व. विद्यालय, बठिंडा– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रवेश देते हैं। पंजाब में किसी समय इंजीनियरिंग का खासा रुझान था। बाहरी प्रदेशों से भी विद्यार्थी पंजाब में बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए आदि में दाखिला लेने के लिए आते थे। पीटीयू में आर्किटेक्चर में 140 सीटें हैं, जबकि इस समय महज 69 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। पीटीयू का खुद का कैंपस तो है, साथ ही में 230 इंजीनियरिंग कॉलेज इसके साथ जुड़े हुए हैं।

अन्य राज्यों पर निर्भरता बढ़ी

पंजाब के तकनीकी कॉलेजों में सीटें न मिलने के कारण बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर–पूर्व और यहां तक कि नेपाल जैसे राज्यों के छात्रों पर निर्भरता बढ़ रही है। पंजाब अनएडेड कॉलेज एसोसिएशन को कट–ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। एसोसिएशन का दावा है कि विभिन्न कारणों से जम्मू–कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर–पूर्व के कई छात्र कट–ऑफ तारीख तक पंजाब के कॉलेजों में सीटें सुरक्षित नहीं कर सके। राज्य के दो तकनीकी विश्व. विद्यालय– आईके गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्व. विद्यालय, बठिंडा – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश देते हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश एआईसीटीई की ओर से विनियमित होते हैं, वहीं पॉलिटेक्निक और आईटीआई में प्रवेश तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से आयोजित किए जाते हैं। जिन पाठ्यक्रमों में कम दाखिले हो रहे हैं, उनमें बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए, बीएचएम के अलावा अन्य शामिल हैं।

प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन के अनुसार प्राइवेट आईटीआई में करीब 45 फीसदी सीटें खाली पड़ी हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश एआईसीटीई की ओर से राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी और सख्त हो। यहां रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए छात्रों के कौशल में सुधार करने का प्रयास किए जा रहे हैं।

पंजाब से पलायन का असर – सरीन

एचएमवी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. अजय सरीन का कहना है कि पंजाब में युवा शिक्षा ग्रहण करने के स्थान पर विदेश को अधिक तवज्जो देता है। यही कारण है कि इसका असर शिक्षा व तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर हो रहा है। पंजाब से भारी संख्या में बच्चे निकल रहे हैं। उनको रोकने के लिए उद्योग लगाए जाने चाहिए।

पंजाब में आईटी व इंजीनियरिंग यूनिट की कमी मुख्य कारण – भाटिया

एचएमवी पत्रकारिता विभाग की डॉ. रमा भाटिया का कहना है कि पंजाब में आईटी इंडस्ट्री नहीं है। पंजाब में उद्योग पलायन कर रहा है। नोएडा, गुड़गांव की तरफ आईटी व इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हो चुके हैं। वहां पर शिक्षा लेना ही विद्यार्थी उचित समझते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग के साथ साथ नौकरी मिल जाती है। यही कारण है पंजाब में विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा लेना नहीं चाहते।

असर तो सीधा पंजाब की तरक्की पर – डॉ. धीरज

दिल के रोगों के माहिर डॉ. धीरज भाटिया का कहना है कि पंजाब में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में सीटें खाली जाने से सबसे अधिक असर पंजाब की तरक्की पर हो रहा है। यहां से जितने भी विद्यार्थी डिग्री लेते भी हैं, तो वह नौकरी पंजाब में नहीं करते। काफी कम लोगों के लिए पंजाब में नौकरी है। नौकरी के लिए तो फिर साउथ, गुरुग्राम की तरफ ही जाना पड़ता है।

पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष राकेश राठौर का कहना है कि मौजूदा सरकार कई झूठे वादे कर सत्ता में आई थी। पंजाब में ज्यादातर कॉलेज भाजपा के शासनकाल में खुले थे, लेकिन बाद में आने वाली सरकारों ने पंजाब के विकास को लेकर बेरुखी दिखाई, जिसका नतीजा सामने है।

सरकार कामकाज से चलती है, बातों से नहीं – परगट सिंह

विधायक परगट सिंह का कहना है कि सरकार बातों से नहीं चलती, जमीनी स्तर पर काम से चलती है। दो सालों से पंजाब की सरकार ने अगर कुछ काम किए होते तो आज पंजाब में आप के उम्मीदवार पार्टी की टिकट छोड़कर नहीं भागते और न ही मंत्रियों को उतारना पड़ता।

पिछली सरकारों ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया – राजविंदर थियाड़ा

पंजाब की आप स्टेट सचिव राजविंदर कौर थियाड़ा का कहना है कि पिछली सरकारों ने पंजाब का हाल बेहाल कर दिया था। अब भगवंत मान की सरकार इसको राह पर ला रही है। यह पिछली सरकारों की देन है कि पंजाब की इंडस्ट्री बद्दी और कठुआ शिट हो गई। पंजाब में पिछली सरक. ारों में नशा फैला और युवा विदेशों की तरफ निकलने लगा।

बादल के समय के पंजाब को आज कहां पहुंचा दिया – चन्नी

अकाली दल के वरिष्ठ नेता गुरचरण सिंह चन्नी का कहना है कि सीएम बादल के कार्यकाल हमेशा विकास के लिए जाने जाते हैं। नया चंडीगढ़ से लेकर आज तो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। यह सब उनकी देन है। पंजाब में तकनीकी शिक्षा की क्रांति का दौर बादल सरकार के दौर आया, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसका हाल बेहाल कर दिया।

पंजाब की सियासी हवा, हर पार्टी को मौका देने में विश्वास रखते हैं पंजाबी

pMhx<A गुरुओं, पीरों, फकीरों और महान बलिदानियों की धरती पंजाब से इंकलाब की आवाज समय समय पर उठती रही है। पंथक, हिंदू, दलित, किसान व डेरे पर आधारित सियासत सूबे पर हावी रही है और पंजाब के अब तक के लोकसभा चुनाव परिणाम के आंकड़े इसे प्रमाणित भी करते हैं। पंजाब के खास इलाकों में खास दलों, खास समुदाय और जातीय समीकरण का दबदबा रहा है। दिलचस्प पहलू यह है कि पंजाबी हरेक सियासी दल को मौका देते हैं। पंजाब ने किसी सियासी दल को निराश नहीं किया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पंजाबी नए प्रयोग करने में आगे रहते हैं।

पंजाब के मतदाताओं ने वामपंथी दलों से लेकर बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, भारतीय लोक दल के नेताओं को भी संसद भवन पहुंचाया है। पंथक राजनीतिक अकाली दल अमृतसर और आम आदमी पार्टी यहां इतिहास रच चुकी है। बसपा के राष्ट्रीय सुप्रीमो दिवंगत कांशीराम से लेकर जनता दल के प्रत्याशी के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल को पंजाब के मतदाता सिर आंखों पर बैठा चुके हैं।

पंजाब में दलितों की आबादी 32 फीसदी है। दोआबा में तो यह 42 फीसदी के करीब है। इसी के दम पर बहुजन समाज पार्टी 1996 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से तीन सीटें जीत चुकी है। होशियारपुर से कांशी राम, फिलौर से हरभजन लक्खा और फिरोजपुर से मोहन सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 1989 व 1991 में बसपा के एक–एक प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। सीपीएम के मंगत राम ने 1977 में फिलौर संसदीय सीट से जीत दर्ज की थी। जबकि सीपीआई के भान सिंह भौरा ने 1999 में बठिंडा से चुनाव जीता था।

जनता दल भी दोआबा के जालंधर में जीत का परचम लहरा चुकी है। जालंधर से पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल दो बार 1989 व 1998 में चुनाव जीते थे।

हेयर बोटॉक्स – डैमेज बाल को बना देता है 10 साल तक जवां

हेयर बोटॉक्स एक ऐसा स्किन हेयर ट्रीटमेंट है, जो आपके बालों को सीधे तौर पर 5 से 10 साल तक जवां बनाता है। आज कल हेयर बोटॉक्स काफी चलन में छाया हुआ है।

बॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन... ये वो सारे हेयर ट्रीटमेंट्स है, जिन्हें लोग बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लेते हैं। लेकिन इन दिनों इन ट्रीटमेंट्स की जगह एक दूसरी एडवांस टेक्नीक ने ले ली है, वो है हेयर बोटॉक्स। बोटॉक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि यह कोई इंजेक्शन वाली प्रक्रिया है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है, जो बालों के रेशों को फिलर यानी केराटिन से कोट करता है। इसे फॉर्मेल्डिहाइड–फ्री ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में ज्यादा केमिकल का उपयोग नहीं होता बल्कि ऐसी चीजें यूज की जाती हैं, जो बालों के लिए फायदेमंद होने के अलावा उन्हें हेल्दी और शाइनी बनाती हैं।

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. कहती हैं कि स्किन बोटॉक्स की तरह ही हेयर बोटॉक्स एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें कोलेजन, विटामिन बी 5 और ई दिया जाता है। यह ट्रीटमेंट बाला. ˋ की बढ़ती उम्र की प्रोसेस को स्लो करने के अलावा पहले से डैमेज हुए बालों को भी अंदर से ठीक करता है। इसमें स्किन बोटॉक्स की तरह इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि बालों पर एक प्रोटीन वाला कंडीशनिंग एजेंट लगाया जाता है।

बाल दिखते हैं बाउंसी

यह बालों की जड़ों में पसीना आने से रोकता है, जिससे बाल चिपचिपे नहीं लगते बल्कि वे बाउंसी लुक देते हैं। वह बताती हैं कि यह ट्रीटमेंट बाला. ˋ की जड़ों से लेकर बालों के आखिरी छोर तक दिया जाता है। इसको लगाने के बाद इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दिया जाता है। बोटॉक्स को धोने के लिए एक सल्फेट फ्री क्लींजर का उपयोग किया जाता है और फिर बालों को ड्रायर से ड्राई किया जाता है।

ठीक हो जाते हैं डैमेज हुए कमजोर बाल

ब्यूटीशियन आरती सिंह बताती हैं यह फॉर्मल्डेहाइड–फ्री और केमिकल–फ्री कंडीशन ट्रीटमेंट है। कैवियार ऑयल, विटामिन बी–5, विटामिन ई और क्वइ्ह्ह्व्ज्ञ्ज– रु पेप्टाइड जैसे केमिकल्स को ज़रूरत के अनुसार मिलाकर बालों पर लगाया जाता है। दरअसल, इसमें गीले बालों पर प्रोटीन–आधारित घोल लगाया जाता है, जो बालों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाने में मदद करता है।

साथ ही, डैमेज हुए कमजोर बालों को ठीक करने में मदद करता है। वह कहती हैं कि साल में इसे दो से तीन बार कराना ही काफी है। अधिक उपयोग करने से बाल टूटने के अलावा, पतले और बेजान हो सकते हैं।

बालों को मिलते हैं बेशुमार फायदे

एक स्टडी के मुताबिक, ट्रीटमेंट की मदद से स्प्लिट एंड की ग्रोथ को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। इससे आपके बालों को केमिकल से हुए नुकसान से भी ठीक किया जा सकता है। बालों को शाइनी और हेल्दी दिखाने के लिए हेयर बोटॉक्स एक बेहतरीन तरीका है। ब्यूटीशियन आरती सिंह के मुताबिक, हेयर बोटॉक्स आपके बालों को मुलायम बनाने के अलावा शाइनिंग भी देता है। बालों को गहराई से पोषण देता है, हाइड्रेशन देता है और साथ ही बालों को स्मूद, चमकदार और घना बनाता है। वह कहती हैं कि बालों के बोटॉक्स ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल होने वाले कोलेजन और केराटिन बालों के क्यूटिकल्स के नुकसान वाले हिस्सों को ठीक करने में मदद करते हैं।

अगर आप अपने बालों को डाई या ब्लीच करना चाहती हैं, तो हेयर बोटॉक्स से पहले करना सबसे अच्छा है।

लंबाई जितनी, खर्चा उतना

हेयर बोटॉक्स का खर्चा बालों की लंबाई के हिसाब से आता है। बाल छोटे हैं, तो आपको इस ट्रीटमेंट के लिए 9 से 12 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं और अगर कमर से नीचे तक हैं, तो यह खर्चा 14 से 18 हजार तक चला जाता है।

असर रहता है पांच से छह महीने

हेयर बोटॉक्स का असर बालों पर लगभग 4 से 6 महीने तक रहता है। हालांकि यह बालों के रखरखाव की दिनचर्या पर भी निर्भर करता है। नियमित टच–अप इसके प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकता है।

ध्यान रखें कुछ बातों का

हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको दो से तीन दिन तक बाल धोने से बचना चाहिए। दरअसल, ट्रीटमेंट का असर बालों पर होने के लिए इतने समय की जरूरत होती है। आप बाल जितने कम धोएंगी, ट्रीटमेंट का असर उतना ज्यादा रहेगा। ट्रीटमेंट के बाद बालों को केवल सल्फेट फ्री शैम्पू से ही धोएं। बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए कंडीशनर यूज करें।

धूप में ज्यादा देर ना रहें

बालों में रोज हीट अप्लाई करने से बचें और ब्लो ड्रायर के बजाय उन्हें खुद–ब–खुद सूखने दें। बालों को हर हते दस दिन में हाइड्रेटिंग मास्क से कवर करें, ताकि डीप कंडिशनिंग मिलती रहे। धूप में ज्यादा एक्सपोज होने पर बाल पहले से रूखे हो सकते हैं। इसलिए धूप में निकलते समय बालों को स्कार्फ या दुपट्टे से कवर करें।

ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ना करें ये गलती

बोटॉक्स ट्रीटमेंट के तुरंत बाद अपने बालों को डाई या कलर न कराएं। बालों को कलर करने से पहले कम से कम दो से हते तक का इंतज़ार करें। परमानेंट डाई में मौजूद केमिकल बालों के क्यूटिकल्स को खराब कर सकते हैं और बोटॉक्स ट्रीटमेंट को बेअसर कर सकते हैं।

उपचार के बाद 24–48 घंटों तक अपने बालों को बहुत कसकर बांधने से बचें।

खोपड़ी पर जमी डैंड्रफ की परत निकाल देगा ये तेल

बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। इसके लिए बालों को झड़ने से बचाने के लिए कुछ उपाय आपके लिए काम कर सकते हैं। गरम पानी से नहाने से बालों की स्कैल्प ड्राई होने लगती है, जिससे बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए बाला. ˋ को झड़ने से बचाने के लिए नेचुरल चीजें उपयोग करें, जैसे भीमसेनी कपूर वाला हेयर ऑयल।

खूबसूरत बाल न सिर्फ दिखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि हमारी सुंदरता में भी चार चांद लगाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार बदलते मौसम की मार या फिर गलत ब्यूटी प्रोडक्ट्स के चयन से बालों में डैंड्रफ की समस्या होने लगती है। जिसका अगर समय पर इलाज न हो, तो स्कैल्प में एलर्जी होने से लेकर बाल तक झड़ जाते हैं। हर बदलता हुआ मौसम अपने साथ ढेरों खुशियों के साथ ढेरों परेशानियां भी लेकर आता है। खासकर सर्दियों के मौसम में जब हम ज्यादा गरम पानी से नहाते हैं , तो वो हमारी स्किन के साथ हमारे स्कैल्प से भी ऑयल को चुराने का काम करती है। जिसकी वजह से स्कैल्प ड्राई होनी शुरू हो जाती है। फिर पपड़ी का रूप लेकर स्कैल्प पर जलन पैदा करने के साथ कई बार बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ बालों की खूबसूरती को बिगाडने का ही काम करते हैं।

और भी चीजें हैं जिम्मेदार

सिर्फ ड्राई या ऑयली स्कैल्प ही नहीं, बल्कि सेबोरहाइक और मलेसेजिया जैसे फंगल इंफेक्शन भी डैंड्रफ के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई बार हार्मोनल परिवर्तन होने की वजह से भी स्कैल्प ड्राई होने लगती है। वहीं हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन, आयरन ,फाइबर व हेल्दी फैट्स का अभाव होने की वजह से बाल कमजोर होने के साथ स्कैल्प पर पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। ऐसे में कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं , जिससे आप आसानी से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं।

कपूर से बनाएं हेयर ऑयल

इंस्ट्राग्राम की एक रील में डैंड्रफ की समस्या के लिए एक कारगर उपाय बताया गया है, जिससे आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल ही जाएगा। इसके लिए आप 2 – 3 भीमसेनी कपूर को अच्छे से क्रश करके, फिर एक बाउल में इसे डालकर इसमें आधा नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें एक कप के करीब गरम नारियल का तेल मिलाकर इसे हते में तीन दिन अपने बालों में 45 मिनट के लिए अप्लाई करें। फिर माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा।

तेल कैसे करता है काम

असल में भीमसेनी कपूर में एंटीफंगल प्रोपर्टीज होती हैं, जो फंगस की ग्रोथ को बढने से रोकने में मददगार है। साथ ही इसकी कूलिंग प्रोपर्टीज स्कैल्प को ठंडक पहुंचाकर जलन को कम करने में मददगार है। और जब हम इसे अपने बालों में अप्लाई करते हैं, तो ये हेयर फोलिकल्स को खोलने में मदद करने के साथ बालों की ग्रोथ में भी सहायक होता है।

वहीं नींबू का रस अपनी एसिडिक प्रोपर्टीज के कारण स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस में रखकर फंगस की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो हुआ न इजी टू मेक के साथ असरदार भी।

कंजूसी में लगाए जा रही हैं एक्सपायर हो चुका मेकअप, चेहरे का हाल बिगड़ते देर नहीं लगेगी

चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम से लेकर काजल तक की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिसके निकल जाने के बाद वह इस्तेमाल के लायक नहीं रहते। लेकिन बहुत सी लड़कियां इन्हें जानें–अनजानें फिर भी यूज करती रहती हैं। एक्सपायरी मेकअप प्रोडक्ट आपकी बॉडी को खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं।

त्वचा में जलन

मेकअप जब पुराना होने लगता है, तब उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिसे लगाने से स्किन पर जलन, रैश और ड्रायनेस हो सकती है। यही नहीं, खराब मेकअप के भीतर बैक्टीरिया का विकास भी होना शुरू हो जाता है।

हो सकती है एलर्जी

यदि आपने कभी एलर्जी का अनुभव नहीं किया, तो भी आपको एक्सपायर्ड मेकअप से एलर्जी हो सकती है।

इनमें सूजन, खुजली और जलन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकतीं।

आंखों में हो सकता है इंफेक्शन

यदि आप गलती से अपनी आंखों में मस्करा या आईलाइनर लगा लेती हैं, तो आपको आई इंफेक्शन जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस का खतरा हो सकता है।

मस्कारा आदि यदि एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके हैं तो उन्हें फेक दें। एक्सपायर्ड मेकअप के बार–बार संपर्क में आने से त्वचा संबंधी पुरानी समस्याएं जैसे डर्मेटाइटिस और समय से पहले बुढ़ापा आने की समस्या हो सकती है।

यदि आपकी स्किन सेंस्टिव है या आपको एक्जिमा की शिकायत रहती है, तो एक्सपायर्ड मेकअप उन्हें और ज्यादा बदतर बना सकता है।

इस रिस्क से खुद को कैसे बचाएं

कोई भी मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसपर लगे लेबल को ठीक से चेक करें। उस पर लिखा यूज बाई नजरअंदाज ना करें।

सिर के बाल पतले हो रहे, गंजापन झलकने लगा है? वापस पाएं अपने खोए बाल

बढ़ते प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। घने, स्वस्थ और चमकदार बाल पाने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल काफी नहीं है। असल में, संतुलित आहार और सही पोषण भी बालों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। आज हम आपको पांच ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बालों को भीतर से पोषण देकर झड़ने से रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं।

बायोटिन

इसे बालों का विटामिन भी कहा जाता है। बायोटिन बालों की मजबूती और उनकी बनावट को बनाए रखने में मदद करता है। यह केराटिन के निर्माण को बढ़ाता है, जो बालों का मुख्य प्रोटीन है। इससे बाल घने, मोटे बनते हैं और कम टूटते या झड़ते हैं।

ओमेगा–3 फैटी एसिड

अलसी के बीज और मछली के तेल में पाए जाने वाले ओमेगा–3 फैटी एसिड घने बालों और स्वस्थ स्कैल्प के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बाला. ˋ के रोमछिद्रों को पोषण देते हैं, स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाते हैं और सूजन को कम करते हैं, जिससे बाल चमकदार और मजबूत बनते हैं।

आयरन

महिलाओं में बालों के झड़ने का एक आम कारण आयरन की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया है। आयरन बालों के रोमछिद्रों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी होता है, जो कोशिकाओं के विकास और मरम्मत में मदद करता है। आयरन सप्लीमेंट लेने से बालों का विकास तेज करने, डैमेज बालों को मजबूत बनाने, घने बाल पाने और आयरन की कमी के कारण होने वाले हेयर फॉल को रोकने में मदद मिल सकती है।

जिंक

यह जरूरी मिनरल स्कैल्प को स्वस्थ रखने और नए बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।

जिंक केराटिन के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो बालों का मुख्य प्रोटीन है। यह रूखेपन और खुजली को कम करता है और स्कैल्प में तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है।

जिंक सप्लीमेंट बालों के रोमछिद्रों को मजबूत बनाने, बालों के झड़ने को कम करने और घने, स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

ध्यान दें कोई भी नया सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

हर व्यक्ति की जरूरतें अलग–अलग हो सकती हैं, जो उम्र, लिंग और मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा, शिक्षा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी,शिक्षा,जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर,शिक्षक से परामर्श लें।

> धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है।
>
> –डॉ० भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

गिरतारी अरविन्द केजरीवाल की

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरतारी भारतीय लोकतंत्र और संघवाद की दिशा के बारे में परेशान करनेवाले सवाल खड़े करती है। आम चुनाव से पहले विपक्ष के एक प्रमुख नेता और एक पदासीन मुख्यमंत्री की गिरतारी की राजनी. तिक मंशा को लेकर कोई शक–शुबहा नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति मामला, जिसमें केजरीवाल को गिरतार किया गया है, अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर ईडी ने धन शोधन की जांच शुरू की। आप के कई अन्य नेता जेल में हैं – मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से और संजय सिंह अक्टूबर 2023 से। अगर ईडी के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत था, तो उसे युद्धस्तर पर मुकदमे को विचारण (ट्रायल) के लिए ले जाना चाहिए था। आरोपियों को जेल में रखकर, जांचकर्ताओं द्वारा अपना खोजी अभियान जारी रखना, कानून से चलने वाले समाज में अस्वीकार्य होना चाहिए। जब आरोपी सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विरोधी हों, तो इन गिरतारियों को कानून को चुनिंदा तरीके से अमल किए जाने के रूप में देखा जायेगा और यह लो. कतंत्र में जन विश्वास को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ईडी से सबूत की एक ऐसी अटूट श्रृंखला मुहैया कराने को कहा था जो यह दिखाती हो कि शराब लॉबी से गलत तरीके से प्राप्त धन सिसोदिया तक पहुंचा था। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि ईडी की योग्यता किसी आरोपी को अपराध से हासिल धन के साथ जोडने वाले निर्बाध सबूत सामने लाने में है। बाद में, उसने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

यह पहली बार नहीं है जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी संवैधानिक पदाधिकारी के पीछे लगी है। हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरतार किये जाने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। जैसे हालात हैं, इस देश की लो. कतांत्रिक राजनीति को केंद्रीय एजेंसियां ठप कर सकती हैं, जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इसे रोजमर्रा का कानून प्रवर्तन मानना जारी रखेंगे। कानून अपना काम कर रहा है . इस बहाने को कोई भी तार्किक व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पायेगा। यह कोई संयोग नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के आरोप में केवल विपक्षी नेताओं को गिरतार कर रही हैं और भ्रष्टाचार के आरोपी नेता भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते ही मुक्ति पा रहे हैं। केजरीवाल ने सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाली एक सर्व–शक्तिसंपन्न एजेंसी के लिए अभियान चलाकर राष्ट्रीय ख्याति पायी थी। एक दशक से ज्यादा समय हुआ जब केजरीवाल और उनके अराज. कतावादी झुंड ने भीड़तंत्र के जरिये संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को चुनौती दी थी और सरकारी खजाने को धारणात्मक नुकसान (नोशनल लॉस) जैसे षड्यंत्रकारी सिद्धांत (कांस्पिरेसी थ्योरीज) को प्रचारित किया था। खुद केजरीवाल अब उस तर्क में फंस गये हैं, जिसे उन्होंने लोकप्रिय बनाया। लेकिन गलत के साथ गलत, सही नहीं होता।

राजनीतिक परिदृश्य और आम चुनाव 2024 का

तमिलनाडु 2019 के उलट, 2024 में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार दिख रहा है। राज्य में डीएमके–नीत मोर्चा एकजुट है, भाजपा–नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) एक और पार्टी पीएमके को साथ लाने में जुटा है, और एआईएडीएमके छोटे संगठनों के साथ रह गयी है। डीएमके नेतृत्व ने अपने सभी सहयोगियों को यथासंभव बढ़िया ढंग से समायोजित करते हुए, उन्हें गठबंधन में बनाये रखा है। राज्य की 39 सीटों में से 22 पर डीएमके किस्मत आजमायेगी। इसमें एक वह सीट भी शामिल है जो कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके) को आवंटित की गयी है और डीएमके के श्उगते सूरजश्व निशान पर लड़ी जा रही है। पहले की ही तरह, कांग्रेस के पास पुडुचेरी समेत 10 सीटें, और दो वाम दलों के पास दो–दो सीटें हैं। अभिनेता रह चुके कमल हासन की अगुवाई वाले एमएनएम को डीएमके गठबंधन में हाल ही में शामिल किया गया है। उसे इस बार कोई सीट तो आवंटित नहीं की जा सकी, लेकिन राज्यसभा सीट का वादा किया गया है। हासन ने सही कदम उठाया है। शायद उन्हें यह एहसास हो गया है कि दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों में से किसी एक का दामन थामे बिना मैदान में टिके रहना लगभग असंभव होगा।

डीएमडीके के अलावा, एआईएडीएमके के पास ऐसा कोई सहयोगी नहीं है जो उसके मत आधार (वोट बेस) में जरा भी योगदान कर सके। छह महीने पहले, उसने भाजपा के राज्य नेतृत्व, खासकर उसके अध्यक्ष के. अन्नामलाई, के साथ मतभेद को लेकर एनडीए छोड़ दिया था। अन्नामलाई ने पूर्व मुख्यमंत्रियों सी. एन. अन्नादुरई और जयललिता की आलोचना की थी। हालांकि ऐसी खबरें आती रही हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व एआईएडीएमके के साथ हाथ मिलाना चाहता है . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जयललिता के बारे में प्रशंसात्मक उल्लेख करते रहे हैं. लेकिन एआईएडीएमके के महासचिव के. पलानीस्वामी भाजपा के साथ कोई ताल्लुक न रखने के अपने संकल्प पर अडिग हैं। नतीजतन, कई पार्टियां ख्जैसे टीएमसी (मूपनार) और पीएमके,, जो 2019 में एआईएडीएमके के साथ थीं, भाजपा की ओर मुड़ गयी हैं। शायद उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन में रहना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। एआईएडीएमके से टूटा समूह, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम करते हैं और टी.टी.वी. दिनाकरन की अगुवाई वाला एएमएमके एनडीए का हिस्सा हैं। पलानीस्वामी ने शायद जैसी कल्पना की थी उसके उलट, उनके यह घोषणा करने के बाद कि वह एक महा गठबंधन्य बनायेंगे, डीएमके–नीत मोर्चे को किसी दल ने नहीं छोड़ा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की ओर उनके दोस्ताना कदम असरदार होंगे या नहीं, यह देखा जाना बाकी है क्योंकि उन्हें डीएमके का समर्थक माना जाता है। एआईएडीएमके अब भी मुख्य विपक्षी पार्टी है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में दो रिक्तियों को भरने में, हड़बड़ी न सही लेकिन, दिखाई गई तेजी को उचित ही आलोचना हुई है। इस बहु–सदस्यीय निकाय को चुनाव आयुक्त (ईसी) अरुण गोयल के इस्तीफे के कुछ ही दिनों के भीतर दो नए सदस्य मिल गए। खुद अरुण गोयल की नियुक्ति भी भारत में चुनावों का संचालन और उसकी निगरानी करने वाले इस आयोग के सदस्यों के चयन की सही मायने में एक स्वतंत्र प्रक्रिया की व्यवस्था से संबंधित एक संविधान पीठ में चल रही सुनवाई के बीच में ही हुई थी। आलोचकों का यह कहना गलत नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला अधिनियम संविधान पीठ के मार्च 2023 के फैसले में परिकल्पित स्वतंत्रता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता मालूम होता है। चुनाव आयुक्तों का चयन ऐसे समय में हुआ जब इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, ष्व्यक्तिगत कारणों‍ष से दिया गया श्री गोयल का इस्तीफा अस्पष्ट बन गया है। यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है कि एक चुनाव आयुक्त, जिसका कार्यकाल पूरा होने में अभी कुछ साल बाकी थे, ने आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने का विकल्प चुना। कहने की जरूरत नहीं कि चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया से जुड़ी चर्चा का दो नए चुनाव आयुक्तों सर्वश्री ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की योग्यता या उपयुक्तता से कोई लेना–देना नहीं है।

असली समस्या उस कानून में निहित है जिसे संसद द्वारा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सवाल उठाये जाने के बाद पारित किया था कि संविधान की स्थापना के बाद से अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत आवश्यक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कोई कानून क्यों नहीं है। अदालत का जोर ईसीआई के कार्यपालिका से स्वतंत्र रहने पर था ताकि आयोग द्वारा कराये जाने वाले चुनाव वास्तव में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इस दिशा में, उसने एक ऐसी अंतरिम व्यवस्था द्वारा शून्य को भरने कोशिश की जिसके तहत प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली एक चयन समिति का गठन हुआ। हालांकि, यह व्यवस्था तभी तक लागू रहनी थी जब तक कि संसद इस संबंध में एक कानून न बना दे। इसी संदर्भ में, सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता केअलावा प्रधानमंत्री और कोई एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया। अदालत के सामने सवाल यह है कि क्या एक ऐसी समिति, जिसमें कार्यपालिका के पक्ष में दो–एक का बहुमत है, सही मायने में स्वतंत्र प्राधिकारी हो सकती है। यह तर्क आकर्षक तो है कि प्रधानमंत्री हमेशा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करते रहे हैं, लेकिन अंततरू एक कार्यपालिका–संचालित प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के वास्ते एक स्वतंत्र निकाय के संवैधानिक सिद्धांत में निहित एक अन्य तर्क के सामने झुकना ही होगा, भले ही एक संस्थागत प्रमुख के रूप में सीजेआई उस चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के सबसे उपयुक्त व्यक्ति न हों।

प्रलोभन पैसों का

वीमेन्स प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के सफल आयोजन के तुरंत बाद, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) होने जा रहा है। इसके 17वें संस्करण का आगाज पिछले चौंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) के बीच मुकाबले के साथ शुक्रवार को चेन्नई में होगा। डब्ल्यूपीएल के दूसरे संस्करण में चौंपियन का ताज आरसीबी के सिर पर सजने से बेंगलुरू की पुरुष इकाई पर अतिरिक्त दबाव होगा, क्योंकि यह एक ऐसी टीम है जिसने अक्सर बड़ी–बड़ी संभावनाएं जगाई हैं लेकिन आईपीएल कभी जीता नहीं है। इस बीच, चीजों की एक आला टीम सीएसके एम.एस. धोनी के चतुराई भरे नेतृत्व और 42 वसंत देखने के बाद एक खिलाड़ी के रूप में प्रासंगिक रहने की उनकी क्षमता के भरोसे रहेगी। टी–20 में धोनी और 41 के होने के बावजूद टेस्ट खेल रहे इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, आधुनिक दौर की फिटनेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में हुई प्रगति को दिखाते हैं। इन दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह ही, आईपीएल ने भी लगातार आगे बढ़ते रहने का नया रास्ता खोज लिया है, चाहे आम चुनाव हो या फिर कोविड–19 महामारी। आयोजन स्थल को दक्षिण अफ्रीका या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ले जाने में लीग प्रबंधन ने तत्परता दिखायी थी, और अब एक और आम चुनाव करीब आने के साथ, यह देखा जाना बाकी है कि अधिकारी इससे कैसे निपटेंगे। अप्रैल 7 तक के मैच सूचीबद्ध किये गये हैं, जबकि बाकी की लीग मई में होनी है। अपने क्लब के लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश के अलावा, देशी और विदेशी सितारों की नजर जून के दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले आईसीसी टी–20 विश्व कप पर रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनाये गये ऋषभ पंत पर भी फोकस रहेगा। वह एक भयंकर सड़क हादसे से उबरे हैं। एक साल से अधिक समय में पंत का ठीक होना इच्छाशक्ति की जीत है और भारतीय टीम में उनकी वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इस टी–20 आयोजन में कैसा प्रदर्शन करते हैं। टीमों के संयोजनों को भी जांचा–परखा जायेगा और इसमें सबसे दिलचस्प होगा मुंबई इंडियंस पर नेतृत्व परिवर्तन का असर देखना, जिसका कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। यह एक ऐसा कदम है जिसकी आलोचना उनके पूर्ववर्ती रोहित शर्मा की फैन ब्रिगेड ने की। साथ ही, इसने जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव जैसे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रभावित किया। सर्वोच्च सम्मान के लिए होड़ कर रही 10 टीमों के साथ, आईपीएल एक विराट वाणिज्यिक आयोजन है। इसका मतलब यह भी हुआ कि कुछ खिलाड़ियों ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से अधिक इस चौंपियनशिप को प्राथमिकता दी। बीसीसीआई को खिलाड़ियों को टेस्ट खेलने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन की पेशकश करनी पड़ी, जो एक विडंबनापूर्ण स्थिति है, क्योंकि उसका बहु–प्रचारित उत्पाद आईपीएल क्रिकेट के दीर्घ प्रारूपों से प्रतिभाओं को निगल रहा है। अभी तक इसे दूसरी टीमों, मुख्य रूप से वेस्टइंडीज, को प्रभावित करने वाले मसले के रूप में देखा गया था। लेकिन, यह समस्या घर के भी काफी करीब तक पहुंच गयी है।

भारत और एमआईआरवी से लैस अग्नि–5

बीते 11 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ही मिसाइल पर कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम देशों के एक छोटे समूह में भारत के शामिल होने का एलान किया। यह उपलब्धि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा मिशन दिव्यास्त्र के तहत मल्टीप्ल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री–एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक से लैस 5,000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता वाली भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि–5 के पहले उड़ान परीक्षण के साथ हासिल की गई। अप्रैल 2012 में अपने पहले परीक्षण के बाद से, अग्नि–5 की हैंडलिंग और संचालन को और ज्यादा आसान बनाने के लिए कैनिस्तराईजेशन सहित कई परीक्षण और विकास हुए हैं। एमआईआरवी प्रणाली के स्वदेशी वैमानिकी (एवियोनिक्स) प्रणाली और उच्च सटीकता वाले सेंसर पैकेज यह सुनिश्चित करते हैं कि पुनः प्रवेश करने वाले वाहन (री–एंट्री व्हीकल) लक्ष्य बिंदुओं तक सटीक तरीके से पहुंचें। डीआरडीओ ने कहा कि इस मिशन ने निर्धारित किए गए सभी मापदंडों को पूरा किया। यह परीक्षण मिशन शक्ति के तहत भारत के पहले एंटी–सैटेलाइट (एसैट) परीक्षण के पांच साल बाद हुआ है। दिनांक 27 मार्च, 2019 को, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के एक संशोधित इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करके लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में एक जीवित उपग्रह को मार गिराया गया था।

यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता है जो भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है और दोबारा हमले की क्षमता को मजबूत करती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत का परमाणु सिद्धांत पहले इस्तेमाल न करने की नीति, न्यूनतम प्रतिरोध पहली बार हमला होने की स्थिति में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई पर आधारित है। सिद्धांत को 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद 2003 में अपनाया गया था। अग्नि–5 पर एमआईआरवी, जो तीन चरणों वाले ठोस ईंधन पर आधारित एक इंजन है, का विकल्प इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इसके दायरे के मद्देनजर यह चीन की ओर केंद्रित है और इसके विविध हथियार इसे मिसाइल रक्षा कवच को भेदने की क्षमता प्रदान करते हैं। देश की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने अपनी पहली निवारक गश्त पूरी कर ली है।

अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया चीन ने 30 जगहों के नाम बदले

chft xA चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी।

हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, इनमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, एक तालाब और एक पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हालांकि, इन जगहों के नाम क्या रखे गए हैं, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया।

पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला हो। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे।

भारत हमेशा कहता है– अरुणाचल हमारा हिस्सा था, है और रहेगा

अरुणाचल में बढ़ते चीनी दखल और यहां की जगहों के नाम बदले जाने पर भारत कहता आया है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है। अप्रैल 2023 में विदेश मंत्रालय ने कहा था– हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आतंरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी।

नाम बदलने के पीछे चीन का क्या दावा है...

दरअसल, चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी। वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत्य का हिस्सा बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है।

चीन अरुणाचल के इलाकों के नाम क्यों बदलता है इसका अंदाजा वहां के एक रिसर्चर के बयान से लगाया जा सकता है।

2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर झांग योंगपान ने ग्लोबल टाइम्स को कहा था, जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वो कई सौ सालों से हैं। चीन का इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज है। पुराने समय में जांगनान (चीन में अरुणाचल को दिया नाम) के इलाकों के नाम केंद्रीय या स्थानीय सरकारें ही रखती थीं। इसके अलावा इलाके के जातीय समुदाय जैसे तिब्बती, लाहोबा, मोंबा भी अपने अनुसार जगहों के नाम बदलते रहते थे। जब जैंगनेम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया तो वहां की सरकार ने गैर कानूनी तरीक. ों से जगहों के नाम भी बदल दिए। झांग ने ये भी कहा था कि अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलने का हक केवल चीन को होना चाहिए।

क्या सच में नाम बदल जाएंगे?

इसका जवाब है– नहीं। दरअसल, इसके लिए तय रूल्स और प्रॉसेस है। अगर किसी देश को, किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे ग्लोबल जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले से जानकारी देनी होती है।

इसके बाद जियोग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का दौरा करते हैं। इस दौरान प्रस्तावित नाम की जांच की जाती है। स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है। तथ्य सही होने पर नाम बदलने को मंजूरी दी जाती है और इसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश को चीन इतना अहम क्यों मानता है?

अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है।चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ–वेस्ट में हैं, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं।

चीनी दावे पर अमेरिका बोला– अरुणाचल भारत का हिस्सा चीन ने यहां सेला टनल का विरोध किया था, इसे अपना इलाका बताया

अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश पर चीनी बयानों के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन के किसी इलाके पर दावे का विरोध करते है।

114 साल में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन

dkjkdlA दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। जुआन वेनेजुएला के रहने वाले थे। फरवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया था। उस वक्त उनकी उम्र 112 साल 253 दिन थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माद. ो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ड्ग पर जुआन की मौत की जानकारी दी। जुआन का जन्म 27 मई 1909 को हुआ था। उनके 11 बेटे, 41 नाती, पोते–पोतियां, 18 पड़पोते–पोतियां और 12 ग्रेट–ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन हैं।

गिनीज की रिपोर्ट के मुताबिक, जुआन वो पेशे से एक किसान थे। उन्होंने बताया था कि उनकी लंबी उम्र का राज कड़ी मेहनत, समय पर आराम करना और रोज एक ग्लास गन्ने से बनी शराब पीना है।

5 साल की उम्र से खेतों में काम कर रहे थे जुआन

5 साल की उम्र में जुआन ने अपने पिता और भाइयों के साथ खेत पर काम करना शुरू कर दिया था। वो गन्ने और कॉफी की खेती में उनकी मदद करते थे। इसके बाद वो शेरिफ (लोकल पुलिस अधिकारी) बन गए और अपने क्षेत्र में जमीन से जुड़े मसले सुलझाने लगे। हालांकि, इस दौरान उन्होंने खेती जारी रखी।

साल 1938 में जुआन ने एडिओफिना गार्सिया नाम की महिला से शादी कर ली। उनकी पत्नी की मौत 1997 में हुई। 2022 में जब जुआन को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया, तब उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। वे कोई खास दवाइयां नहीं लेते थे। हालांकि, ज्यादा उम्र की वजह से जुआन ऊंचा सुनते थे।

जुआन को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी उन्हें अपने बचपन की ज्यादातर बातें भी याद थीं। उन्हें केक, सूप और एवोकैडो खाना बेहद पसंद था। स्पेन के सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 18 जनवरी 2022 को 112 साल और 341 दिनों की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद जुआन को दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब मिला था।

जुआन का जन्म 27 मई 1909 में हुआ था। उन्हें 112 साल 253 दिन की उम्र में दुनिया का सबसे बुजुर्ग शख्स घोषित किया गया था।

जुआन का जन्म 27 मई 1909 में हुआ था। उन्हें 112 साल 253 दिन की उम्र में दुनिया का सबसे बुजुर्ग शख्स घोषित किया गया था।

पिछले साल सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हुआ था

इससे पहले पिछले साल मार्च में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ था।

साउथ अफ्रीका में रहने वाली जोहाना माजिबुको 128 साल की थीं। उनका जन्म 1894 में हुआ था। जोहाना के 7 बच्चे, 50 से ज्यादा नाती, पोते–पोतियां और पड़पोते–पोतियां हैं।

जोहाना ने कभी पढ़ाई नहीं की थी। वो खेतों में काम करती थीं।

उन्होंने 1914 में हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 में हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा। स्पैनिश लू से लेकर कोरोना महामारी का सामना किया था।

केजरीवाल की गिरतारी पर मुखर, पाकिस्तान में इमरान खान पर चुप्पी क्यों?

o,f'kxVuA अमेरिका ने बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की गिरतारी पर बयान जारी किया था। अब बुधवार को अमेरिका के विदेश विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके प्रवक्ता मैथ्यू मिलर फंसते नजर आए। दरअसल एक पत्रकार ने अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से पूछा कि अमेरिका, भारत में अरविंद केजरीवाल की गिरतारी पर मुखर है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की गिरतार पर उसने चुप्पी क्यों साधी हुई है?

सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमने कई बार कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सभी लोगों के साथ कानून और मानवाधिकारों के मुताबिक बराबरी का व्यवहार किया जाए। दुनिया के किसी भी देश के मामले में हमारा यही स्टैंड है।श जवाब से साफ है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने जवाब से बचने की कोशिश की। उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरतार किया गया है, जिस पर अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल दें। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से जब गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और वे भारत में चल रही इस मामले की जांच पर भी नजर बनाए हुए हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि श्हमने भारत सरकार को साफ कर दिया है कि हम इस मामले की विस्तृत जांच चाहते हैं और हम भारत की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास इसे लेकर कोई अपडेट्स नहीं हैं।श हाल ही में अमेरिका के भारत में राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा था कि कोई भी सरकार या सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे देश के नागरिक की हत्या की साजिश में शामिल है तो यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और यह रेड लाइन है।

अमेरिका का नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत में एक घोषित खालिस्तानी आतंकवादी है।

बीते दिनों निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को चेक गणराज्य में गिरतार किया गया था। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि निखिल गुप्ता ने गुरपतवंत सिंह को मारने की साजिश रची। ये भी दावा किया गया कि निखिल गुप्ता भारत सरकार के अधिकारी के संपर्क में था। अमेरिका के दावे के बाद भारत ने मामले की जांच की बात कही।

मुस्लिम नहीं आए बाइडेन की पार्टी में व्हाइट हाउस को कैंसिल करना पड़ा रमजान सेलिब्रेशन

o,f'kxVuA गाजा में चल रही जंग में इजराइल का समर्थन करने से अमे. रिका के मुस्लिम नेता बाइडेन प्रशासन से नाराज हैं। इसका असर व्हाइट हाउस के रमजान सेलिब्रेशन पर भी पड़ा है। अमेरिका के मुस्लिम नेताआ. ं ने बाइडेन की इफतार पार्टी का न्योता ठुकरा दिया। इसके चलते बाइडेन को रमजान सेलिब्रेशन कैंसिल करना पड़ा।जबकि पिछले साल व्हाइट हाउस में हुई रमजान पार्टी में लोगों ने बाइडेन को आई लव यू कहा था। इस बार हालात बिल्कुल उलटे हैं। मुस्लिमों ने विरोध जताते हुए व्हाइट हाइस के बाहर नमाज पढ़ी। बाइडेन को अपने रमजान डिनर के लिए व्हाइट हाउस में ही काम करने वाले मुस्लिम अधिकारियों को जुटाना पड़ा। इन अधिकारियों के साथ डिनर से पहले बाइडेन ने कुछ मुस्लिम नेताओं से मीटिंग की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुस्लिम नेताओं ने गाजा में जंग पर अपनी बात रखी। कुछ तो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर निकल गए। बाइडेन से मुलाकात करने वालों में फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी डॉक्टर थायर अहमद भी थे। उन्होंने कहा कि डिनर टेबल पर खाना खाते हुए आप भुखमरी की बात कैसे कर सकते हैं।

किडनी रैकेट का भंडाफोड गुरुग्राम में, जयपुर के अस्पताल में निकाली गई बांग्लादेशी की किडनी

x#xkeA हरियाणा की गुरुग्राम में सीएम लाइंग टीम ने सेक्टर 39 के एक होटल पर रेड कर किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

मौके से एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है, जो किडनी बेचने के लिए यहां पहुंचा था। जयपुर के अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज को होटल में शिट किया गया था।

गुरुग्राम के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. पवन चौधरी के मुताबिक सीएम लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर–39 के बाबिल पाला होटल में रेड की। यहां से पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू किया।

इसकी किडनी को जयपुर फोर्टिस अस्पताल में निकाला गया था।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि व्यक्ति की डील एक एजेंट के जरिए चार लाख टका में हुई थी।

जयपुर में ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत होने की बात कहकर उसे गुरुग्राम के इस होटल में शिट कर दिया गया था।

इसी होटल में उसका इलाज चल रहा था।

सीएम लाइंग को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में एक होटल में किडनी प्रत्यारोपण रैकेट चल रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक टीम गठित कर सेक्टर–39 के बाबिल पाला होटल में रेड की गई।

यहां शमीम नामक व्यक्ति मिला। उसकी किडनी निकाली जा चुकी थी। शमीम ने बताया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है और वहां मोबाइल शॉप चलाता है। फेसबुक पर किडनी प्रत्यारोपण का विज्ञापन देखकर उसने एजेंट से संपर्क किया था।

बांग्लादेशी युवक ने बताया कि बांग्लादेशी करेंसी के मुताबिक उससे चार लाख टका में किडनी देने का सौदा तय किया गया था।

यह राशि लेकर उसने किडनी देने के लिए डील फाइनल कर दी।

एजेंट ने ही उसके फिंगर प्रिंट लेकर उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया और करीब दो महीने पहले भारत भेज दिया। यहां उसका फोर्टिस अस्पताल जयपुर में ऑपरेशन किया गया।

कुछ दिन पहले ही उसे गुरुग्राम में शिट किया गया है।

गुरुग्राम सदर थाना प्रभारी अर्जुन देव का कहना है कि मामला बेहद संवे. दनशील है। ऐसे में तथ्यों के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल शमीम से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है कि आखिर वह किस एजेंट के जरिए गुरुग्राम आया था।

बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जैसे–जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे–वैसे आगामी कार्रवाई की जाएगी।

p स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर बलॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com